(कुमार विकल की कविताएं)

अंग–संग (रंग खतरे में हैं।)

मेरे अंग–संग रहो
मेरे प्रिय जनो!
मेरी हिफ़ाजत करों
मुझे इस समय तुम्हारी इतनी जरूरत है
जितनी युद्ध में सिपाही को अपने हथियार की होती है।
दुश्मन नयी साजिशें चल रहा है
हमारे साथियों को
छोटे–छोटे लालचों से
अपने पक्ष में कर रहा है।

मेरे प्यारे कामरेड, रामाचल!
आ, तू अपनी पूरी जमात के साथ आ
मेरी ढाल बन
मेरे अंग–संग चल
इन कमजोर क्षणों में
तू मुझे दे इतना बल
कि भूल जाऊं मैं
उन दोस्तों का छल
जो कर गये हैं हमसे घात
और छोड़ा है उस समय हमारा साथ
जब शब्द ठीक काम करने लगे थे
और शब्दों की ताकत से
हम ठीक हथियार गढ़ने लगे थे।

कामरेड रामाचल,
शब्द और हथियार का इस्तेमाल
हजारों कंठों
लाखों हाथों की मांग करता है
इसलिए साथियों के छूट जाने का भाव
एक जख्म तो करता है।

आओ
हम अपने–अपने जख्म
एक दूसरे को दिखायें/सहलायें
लेकिन इन्हें अपनी जमात से बिलकुल न छिपायें
मरहम तो, आखिर जमात ही लगायेगी
एक मां की तरह आंसुओं को पोंछेगी
दुलरायेगी
और फिर पीठ ठोंक कर
हमारी शक्ति को बढ़ायेगी।

पेज 1 का शेष भाग

बलात्कार के बहाने व्यवस्था पर उगला गुस्सा, नज़ला सारा पुलिस पर

इस पूरे खेल में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में पुलिस को निशाने पर लिया गया है। इस हकीकत को कोई समझना नहीं चाहता कि वास्तव में पुलिस संगठन है क्या और इसके ज़िम्मे काम क्या लगा रखा है? पुलिस शासक वर्गों द्वारा गठित एक ऐसा संगठन है जिसका एक मात्र उद्देश्य शासक वर्गों के हितों की हर तरह से रक्षा करना तथा आम आदमी को डंडे से हांकना। अंग्रेजी राज में भी यही उद्देश्य था और देशी अंग्रेजों के राज में भी यही। पुलिस की भर्ती, ट्रेनिंग व तैनाती तक की सारी प्रणाली भ्रष्टाचार में डूबी है। जो पैसा दे कर भर्ती व तैनाती पायेगा वह वसूली तो करेगा ही। रही बात सुरक्षा की तो वह केवल वी आई पी के लिये है। सोनिया परिवार की सुरक्षा के लिये एस पी जी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) है। इसमें तैनात करीब 2000 अफ़सरों व जवानों का सालाना बजट 500 करोड़ से ऊपर है। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल परिवार की सुरक्षा सेवा में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। तमाम मन्त्रियों, सांसदों, विधायकों, विपक्षी नेताओं, जजों की सुरक्षा में तो पुलिस तैनाती है सो है पोंटी चड्ढा व नामधारी जैसे अपराधी भी पुलिस सुरक्षा ले कर चलते हैं। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि पुलिस का एक बड़ा भाग वी आई पी सुरक्षा में तैनात रहता है शेष बाकी दिखावे मात्र के लिये आम जनता की सुरक्षा के नाम पर उसे लूटने व पीटने के लिये छोड़ रखा है।

आम आदमी की जो थोड़ी बहुत सुरक्षा हो भी रही है, वह इनकी मजबूरी है। इस मजबूरी के पीछे जनता के विद्रोह व आक्रोश का वह भय है जो आज सामने आ ही गया। मौजूदा इस मामले में 48 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को व अगले 72 घंटों में शेष 2 आरोपियों को पकड़ कर सराहनीय काम किया है। सूचना मिलने के बाद मात्र 10 मिनट में सड़क पर नंगे पड़े पीड़ितों के पास पहुंच कर उन्हें ओढने को चादर देना और तुरंत अस्पताल में दाखिल कराना तो और भी सराहनीय काम था। लेकिन यह पुलिस यदि उस रामाधार की शिकायत पर सक्रिय हो जाती, जिसको उसी बस में सवार गुंडों ने लूटा था, तो दुष्कर्म की यह इतनी बड़ी घटना न हुई होती। इसके लिये पुलिस संसाधनों व स्टाफ़ की कमी को कारण बता सकती है जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है। इसके लिये शासक ज़िम्मेदार हैं न कि उनकी पुलिस।

इस तरह के तमाम अपराधों के लिये यदि कोई ज़िम्मेदार है तो वह है सरकार तथा वह समाज जिसने निकम्मो व भ्रष्टाचारियों के हाथ में सत्ता सौंप रखी है, न कि पुलिस। समाज में गुंडों व अपराधियों को संरक्षण दे कर पालने पोसने वाले नेता लोग खुद अपने चारों ओर पुलिस का सुरक्षा कवच तैनात कर लेते हैं तथा आम जनता को उन अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं मौजूदा जनाक्रोश उभरने पर सारी अला-बला पुलिस के मत्थे मढ कर खुद पाक साफ़ बने रहने का ढोंग रचते हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और न ही इसे केवल पुलिस एवं आपराधिक न्याय व्यवस्था के द्वारा रोका जा सकता है। यह एक व्यापक सामाजिक समस्या है। इसकी गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि देश भर में बलात्कार के विरूद्ध व्यापक जनाक्रोश के बावजूद इसी एक पखवाड़े में बलात्कार व छेड़छाड़ की अनेकों घटनायें हो चुकी हैं। कोई दिल्ली में तो कोई असम में कोई भिवानी में तो कोई कोलकत्ता में और न जाने कहां कहां लगातार हुई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की भयंकर फ़जीहत से भी पंजाब की पटियाला पुलिस ने कोई सबक लेने की जरूरत नहीं समझी जिसके चलते नाबालिग पीड़िता को आत्महत्या करनी पड़ी। पुलिस यदि ठीक हो ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ हो तो महामारी का रूप ले चुके महिला-अपराधों के प्रति केवल एक अच्छे डाक्टर की भूमिका ही निभा सकती है, जो कि पर्याप्त नहीं है। जब तक महामारी की उत्पत्ति एवं फ़ैलाव को नहीं रोका जायेगा तब तक इसे संभाल पाना अकेले पुलिस के बस का हो ही नहीं सकता। इसके लिये जरूरी है लिंगानुपात को ठीक करना, सामाजिक विषमताओं को समाप्त नहीं तो कम से कम करना और शिक्षा के द्वारा उचित संस्कारों के साथ जागरूकता को बढाना। महिला सशाक्तिकरण के नाम पर पाखंड तथा नौटंकी करने के बजाये ठोस काम की जरूरत है। आज शायद ही कोई घर हो जहां बेटे और बेटी में भेद-भाव न किया जाता हो। बेटी को शुरू से ही बताया जाता है कि उसे तो भगवान ने ही कमजोर अबला बनाया है, इसलिये उसे सदैव अपनी रक्षा हेतु किसी पुरूष पर निर्भर रहना होगा। जब तक वह इस तरह के संस्कारों से मुक्त हो कर सबला एवं स्वावलंबी नहीं बनेगी तब तक उस पर होने वाले अत्याचारों को रोक पाना कठिन ही नहीं नामुमकिन है।

कोख से लेकर कैपिटल तक तू कहां महफूज है, भेड़ियों की बस्ती में शेरनी बनकर रहना सीख ले...

न्यायपालिका भी कम दोषी नहीं

मौजूदा जनाक्रोश में पुलिस की बेवजह फ़जीहत को देखते हुए अपने नम्बर बनाने के लिये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस पर चढाई कर दी। पहले सटेटस रिपोर्ट मांगी, फ़िर फ़टकार लगाते हुए दूसरी रिपोर्ट मांगी, क्योंकि पहली रिपोर्ट में किसी पुलिस अधिकारी को दोषी बता कर सज़ा नहीं दी गयी थी। हाई कोर्ट कें झूठे अहम को सन्तुष्ट करने के लिये ए सी पी ट्रेफ़िक तथा ए सी पी कंट्रोल रूम सहित 3 अन्यों को दोषी बता कर निलम्बित कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि पुलिस मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में बैठने वाले ए सी पी का इस बलात्कार से क्या लेना देना?

जो हाई कोर्ट पुलिस पर गर्मी खा रही है वह अपने भीतर झांक कर क्यों नहीं देखती? उसकी अदालतों में अन्य मुकदमों के अलावा दस हज़ार से अधिक बलात्कार के मुकदमें बरसों से क्यों लम्बित पड़े हैं? क्या अदालतों का काम केवल तारीख पर तारीख देना रह गया है? इनमें बैठे जजों को यदि इनकी हकीकत का शीशा दिखा दिया जाये तो इनका 'अपमान' हो जाता है। अवमानना का मुकदमा खड़ा हो जाता है। समाज ने भी इन्हें राम जी की पवित्र गाय का दर्जा दे रखा है। सरकार, पुलिस व अन्य जिस महकमे को जितनी मर्जी गालियां कोई दे ले, परन्तु इनके खिलाफ़, चाहे जितना रोष्प हो, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन यह स्थिति सदा रहने वाली नहीं। यदि न्यायपालिका के बढते पतन को जल्द न रोका गया तो जल्द ही इनका जुलूस भी निकलना शुरू हो जायेगा।

आग बुझने के बाद भी जलाते हैं निगमकर्मी

परन्तु इस मामले में पीड़ित पार्टी चूंकि दमकल एवं निगम अधिकारियों पर भारी पड़ गयी इस लिये जब चंडीगढ से डंडा फटकारा गया तो तुर्त फुर्त मुफ़्त में ही यानी बिना रिश्वत के रिपोर्ट बनाकर देने के आदेश हुए। आदेश तो हो गये, परन्तु जिस नंदा नामक दमकल अधिकारी ने बिना रिश्वत खाये कभी रिपोर्ट जारी न की हो, वह इतनी आसानी से मुफ़्त में रिपोर्ट कैसे बना दे? भारी ऊपरी दबाव के बावजूद नंदा ने एक सप्ताह तक हाथ पांव फड़फडाये। उसके बाद रोते पीटते जो रिपोर्ट बनाई वह भी ग़लत। दोबारा फ़िर जब फटकार पड़ी तो अगले दिन बड़े भारी मन से उसने ठीक रिपोर्ट बना कर दी। दरअसल इसके लिये अकेले नंदा को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है। इसके लिये वे सब अधिक दोषी हैं जिन्होंने नंदा को पाल पोस कर इस पद पर बैठा रखा है, वरना उसकी क्या मजाल जो स्वत: तुर्त फुर्त काम न कर के दे। कहने की जरूरत नहीं कि उसका पालन-पोषण करने वाले भी लूट में से अपना हिस्सा बाकायदा वसूलते हैं। लेकिन आम आदमी को निचोड़े बिना यहां से रिपोर्ट नहीं मिल सकती। यहां से क्या आम आदमी को तो कहीं से भी कुछ नहीं मिल सकता, चोरों के इस राज में।

गौरतलब बात यह है कि जब 15 वर्ष पूर्व सरकार ने प्रत्येक गैर रिहायशी भवन पर फ़ायर टैक्स लगा दिया, जिससे करोड़ों रुपया वार्षिक वसूली होती है तो फ़िर किसी से आग लगने पर बिल वसूली का क्या मतलब है? कुल मिला कर निष्कर्ष यह निकलता है कि सरकार व उसके कर्मचारियों का तो एक सूत्री कार्यक्रम किसी न किसी बहाने से जनता को लूटना है और वह लूट रही है।

इस एक गैंगरेप पर हंगामा क्यूं है बरपा...

बहरहाल, मुद्दा यह है कि अब क्या हो? हुक्मराम परेशान हैं और जनता भी आजिज आ गई है। सभी चाहते हैं कि कुछ न कुछ हो, पर क्या हो? अभी तो आग लगी है, भड़कती जा रही है, वाटर कैनन से बुझने वाली नहीं। हुक्मराम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा कर मामले को रफ़ा-दफ़ा करना चाहते हैं, पर कमिश्नर साहब ने कह दिया कि वे नहीं हटेंगे।

दिल्ली के लाट साहब विदेश यात्रा अधूरी छोड़ वापिस आये, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा कि वे आ गए हैं और मामले को देखेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अनिच्छापूर्वक ही सही, बयान दिया। सोनिया ने कहा होगा बयान देने के लिए। नेताओं का काम ही है बयान देना।

पिछले दिनों रेप को लेकर नेताओं के अजीबोगरीब बयान आते रहे हैं। ऐसे भी बयान आये कि चाऊमिन के कारण रेप बढ़ रहे हैं। कुछ का मानना है कि जीन्स और उसमें भी टाइट जीन्स रेप का एक बड़ा कारण है। पर जीन्स पहनने वाली कम ही लड़कियों से बलात्कार होते हैं। देहातों में, स्लम बस्तियों में शलवार और साड़ी पहनने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं। बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ भी। और दुधमुंहीं बच्चियों में क्या सेक्स अपील होती है, उनमें काम वासना भड़काने वाली क्या बात होती है, जो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता।

तो बलात्कार की समस्या की जड़े बहुत ही गहरी हैं। हमारे समाज में, संस्कृति में। सतही समाधान संभव नहीं। क़ानून बलात्कार को नहीं रोक सकता। क़ानून अंधा होता है। एक खास बात यह है कि दिल्ली के राजपथ पर बलात्कार का विरोध करने जुटी हज़ारों की भीड़ में कोई ग़रीब आदमी नहीं दिखा। यह एक सवाल भी है। और बलात्कार की इस वारदात से 'व्यथित' भाजपा नेता और मध्यप्रदेश के नगरीय विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि पूरे देश में पुरूषों और महिलाओं के लिये एक ड्रेसकोड निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी बलात्कार की समस्या का संबंध महिलाओं के पहनावे से हैं? तब तो कचरा बीनने वाली महिलाओं के साथ तो कतई बलात्कार नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे फटे-चीथड़े पहने होती हैं और उनके शरीर से बास भी आती है।